





भाग II—वण्ड 3—उप-वण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार के प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629

नई विल्ली, रानिवार, अक्तूबर 26, 1991/कालिक 4, 1913

No. 629] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 26, 1991/KARTIKA 4, 1913

1 122 122 122 122

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ तंक्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में रक्षा जा सर्वे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 26 श्रक्तूबर, 1991

का.आ.729(अ).—पीपुल्स लिबेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र) जो माद्यारणतया पी.एल.ए. के नाम से जात है, पीपुल्स रेवोल्यू-शनरी पार्टी ऑफ कांगलीणक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रेपक कहा गया है) और उसकी "रेड आर्मी" नथा प्रेपक की अन्य शाखाएं भी, जैसे कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी मशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है और यूनाइ-टेड नेशनल लिबेशन फंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामृहिक एप से मैंनई उग्रवादी संगठन कहा गया है)—

(i) अपने उद्देश्य के रूप में खुले रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वे एक स्वतंत्र मिणपुर का गठन करेंगे जिसमें मिणपुर का राज्य समाविष्ट होगा तथा जिन्होंने उक्त राज्य को भारत के संघ से विलग करने के भ्रमने उद्देश्य के श्रन्सरण में हिमात्मक कार्र-वाइयां प्रारंभ कर दी है:

- (ii) सशस्त्र बलों, अर्थात्, पीपुल्स लिबेशन आर्मी, रैड आर्मी के नाम से झात बलों, उनके सदस्यों तथा उनके द्वारा स्थापित श्रन्य निकायों का उपयोग अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं;
- (iii) ग्रापने उपर्यक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उक्त भस्त्र बलों, उनके सदस्यों का उपयोग मणिपुर के राज्य के सुरक्षा बलों भौर सिविल सरकार तथा नागरिकों पर ग्राक्रमण करने के लिए कर रहे हैं; श्रीर सिविल श्राबादी के विरुद्ध लूट श्रीर ग्राभितास तथा ग्रापने संगठनों के लिए निधि संग्रह करने के कार्यों में लगे हए हैं;
- (iv) अपने उपर्यक्त उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए; शस्त्र श्रीर प्रशिक्षण के रूप में सहायता पाने के

लिए, विदेशों के साथ संपर्क करने के श्रपने प्रधास पुनः प्रारंभ कर चुके हैं;

श्रीर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपर्युक्त कारणों से मेतई उग्रवादी संगठन श्रीर उनके द्वारा गठित श्रन्य निकाय, जिनके श्रन्तगंत अपर नामित संगस्त्र समूह भी है, विधि विरुद्ध संगम है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार की यह राय भी है कि उपर्युक्त मेर्तर्ब उग्रवादी संगठनों के मशस्त्र ममूहों द्वारा पृलिस बलों ग्रीर सिविल ग्राबादी पर हमलों ग्रीर हिंसा के लगातार कार्यों के कारण यह ग्रावण्यक है कि मेर्तर्ब उज्ञवादी मंगठनों ग्रीर उनके द्वारा स्थापित ग्रन्थ लिकायों की, जिनके ग्रन्तगंत ज्यर नामित सगस्व नमूह भी है, तुरन्त प्रभावी हप से बिजिबम्द्ध घोषित किया जाए;

त्रतः, भन्न, केन्द्रीय गण्कार, विधिविक्द क्रियाकलाप (निवारण) प्रधिनियः, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीपुल्स लिश्रेसन श्रामी (पूर्वी क्षेत्र), पीपुल्म रेवोल्यूसनरी पार्टी ग्राफ कांगलीपक, श्रीर उसकी रैंड श्रामी, तथा प्रेपक के अन्य उपवलों को भी, जैसे कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी श्रीर उसका समस्त्र विष्य, जो रैंड श्रामी भी कहलाता है, श्रीर उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों तथा यूनाइटेड नेजनल लिप्रेशन फंट को त्रिधिविच्द्व संगम घोषित करती श्रीर उस धारा की उपधारा (3) के पण्लाक द्वारा प्रदन्त प्रवितयों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त श्रिधियम की धारा 4 के श्रिधीन बनाए गए किसी श्रादेश के अधीन रहते हुए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं.-1\/34/91-एन.ई.-1] विनय शंकर, संयुदन सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1991

S.O. 729(E).—Whereas the People's Liberation Army (Eastern Region), generally known as the PLA, the People's Revolutionary Party of Kangleipak (hereinafter referred to as PREPAK) and its 'Red Army' as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party and its armed wing also called the 'Red Army' and the United National Liberation Front (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations)—

(i) have openly declared as their 'objective the formation of an independent Manipur comprising the State of Manipur and have resorted to violent activities in pursuance of their objective to bring about cession of the said State from the 'Union of India';

- (ii) have been employing armed forces, namely, the so called People's Liberation Army, the Red Army, their members and the other bodies set up by them, to achieve their aforesaid objective;
- (iii) have in furtherance of their aforesaid objective been employing the said armed forces and members in attacking the Security Forces and the Civil Government and the citizens in the State of Manipur, and including in acts of looting and intimidation against the civilian population for collection of funds for their organisations;
- (iv) have some efforts to resume their contracts with fereign countries for securing assistance by way of a.ms and training for the purpose of achieving their aforesaid objective.

And, whwereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations;

And, whereas, the Central Government is further of the opinion that because of the repeated acts of violence and attacks by armed groups and members of the Meitei Extremist Organisations on the eccurity forces and on the civilian population, it is necessary to declare the Meitei Extremist organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the People's Liberation Army (Eastern Region), People's Revo-Iutionary Party of Kangleipak and its Red Army as also offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party and its armed wing also called the Red Army and other bodies set up by them and the United National Liberation Front to be unlawful associations, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that Section that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

> [F. No. 11/34/91-NE I] VINAY SHANKAR, Joint Secy. (NE)